पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या-461

थाना मामला संख्या-42 वर्ष-2020 थाना-महिला थाना, जिला-वैशाली, से उत्पन्न

==========

संगीता देवी उर्फ संगीता देवी, पत्नी-संत लाल साह, निवास, गाँव-मौदाह बुजर्ग, थाना-पाटेपुर, जिला- वैशाली (बिहार)।

.... अपीलार्थी

बनाम

1. बिहार राज्य
2. 'एक्स. सी./ओ. भूलान राय, निवासी, गांव और डाकघर-मोदाह बुजर्ग, थाना-पाटेपुर, जिला– वैशाली।

.... उत्तरदाता

==========

के साथ

2022 का आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या-546

थाना मामला संख्या-42 वर्ष-2020 थाना-महिला पी. एस. जिला-वैशाली, से उत्पन्न

==========

संजीत पासवान, पुत्र-बिशुनी पासवान, निवास-गाँव और पोस्ट- मौदाह बुज़ुर्द , वार्ड संख्या 10, पुलिस स्टेशन-पाटेपुर और जिला-वैशाली (बिहार)

.... अपीलार्थी

बनाम

1. बिहार राज्य
2. 'एक्स. सी./ओ. झूलन राय, महुदाह, पी. एस.-पाटेपुर, जिला-वैशाली के निवासी ।

....उत्तरदाता

==========

उपस्थिति :

(2022 के आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 461 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : सुश्री शमा सिन्हा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं की अधिवक्ता : सुश्री शशि बाला वर्मा, एपीपी

(2022 का आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 546 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री मनीष कुमार नं. 2, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : सुश्री शशि बाला वर्मा, एपीपी

==========

भारतीय दंड संहिता, *1860*—धारा *376(2)*(एन) और *109*—बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, *2012*—धारा *5(1), 5(j)(ii)* और *6/17*—अपीलकर्ता ने पीड़िता के साथ लगभग छह महीने तक बलात्कार किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई—अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल नहीं रहा कि अभियोजन पक्ष की पीड़िता घटना की तिथि पर नाबालिग थी—अपीलकर्ताओं को संदेह के लाभ पर अधिनियम, *2012* की धारा *6* के तहत आरोप से बरी किया गया—अभियोजन पक्ष यह भी साबित करने में असफल रहा कि अपीलकर्ता *(461* में*)* ने पीड़िता पर बलात्कार की कथित घटना को सुविधाजनक बनाया—अपीलकर्ता *(461* में*)* को धारा *376(2)*(एन)*/109* भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप से संदेह के लाभ पर बरी किया गया—अपीलकर्ता *(546* में*)* पीड़िता से जन्मे बच्चे का जैविक पिता पाया गया—अपीलकर्ता *(546* में*)* ने कभी पीड़िता के साथ सहमति से यौन संबंध का दावा नहीं किया—अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता *(546* में*)* के खिलाफ धारा *376(2)*(एन) आईपीसी के तहत अपना मामला स्थापित किया —अपीलकर्ता *(546* में*)* की धारा *376(2)*(एन) के तहत सजा बरकरार है—सजा और आदेश में संशोधन किया गया। सीआरएल. रेफ. *2/2024*—निर्भर किया गया।

2018 एसीसी ऑनलाइन दिल्ली*10448; 2023* एससीसी ऑनलाइन दिल्ली*2782; 2023* एसीसी ऑनलाइन दिल्ली *5852*—संदर्भित किया गया।

(2021) 15 एससीसी *241; (2018) 9* एससीसी *248*—सुभिन्न किया गया।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

गणपूर्ति/समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक जजमेंट

(प्रतिःमाननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

तारीख : 23-01-2025

इन दोनों अपीलों को दिनांकित 18.04.2022 के दोषसिद्धि (इसके बाद 'आक्षेपित/विवादित निर्णय' के रूप में संदर्भित) और 22.04.2022 के सजा/दोषसिद्धि के आदेश (इसके बाद 'आक्षेपित/विवादित आदेश' के रूप में संदर्भित) को दरकिनार/रद्द करने के लिए /प्रस्तुत की गई है, जो कि हाजीपुर में विद्वान विशेष न्यायालय, पॉक्सो-सह-ए. डी. जे.-VI, वैशाली द्वारा 2020 के महिला पी. एस. मामले संख्या 42/पॉक्सो जी. आर. संख्या 2020 में पारित किया गया (जिसे इसके बाद 'विद्वान विचारण अदालत' के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसके द्वारा

और जिसके तहत विद्वान विचारण अदालत ने अपीलकर्ता संगीता देवी और संजीत पासवान को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (संक्षेप में 'पॉक्सो अधिनियम') के तहत साथ ही भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है। अपीलार्थी संजीत पासवान को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(1) और 5(जे)(ii) के तहत किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत और आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) के तहत भी दंडनीय है। अपीलार्थी संगीता देवी को पीड़ि 'एक्स' के शरीर पर गंभीर भेदक/प्रवेशन यौन हमले के अपराध के लिए उकसाने के लिए दोषी पाया गया है जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 6/17 के तहत दंडनीय है। उसे आई. पी. सी. की धारा 109 की सहायता से धारा 376 (2) (एन) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

<u>अभियोजन का मामला</u>

2. अभियोजन पक्ष की कहानी पीड़ित ('एक्स') के लिखित आवेदन (प्रदर्श 'पी-1/पीडब्लू-1') पर आधारित है। अपने लिखित आवेदन में उसने कहा है कि उसके पिता मानसिक रूप से बीमार हैं और आठ साल पहले उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उसकी चाची उसकी देखभाल कर रही है। आरोपी संजीत पासवान शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। आरोपी संगीता देवी और उसकी बेटी आंचल कुमारी, संजीत पासवान के निर्देश पर, उसे अपने घर ले जाने के लिए लुभाते थे। अभियुक्त संजीत पासवान उसे पैसे देने के बहाने उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन जब उसने विरोध किया तो उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। डर के मारे/भय से, उसने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। संजीत पासवान ने लगभग छह महीने तक उसके साथ बलात्कार किया जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। संजीत पासवान संगीता देवी के साथ ब्याज के आधार पर पैसे का लेन-देन करता था। इस कारण से, उनके कहने पर, संगीता देवी उन्हें फोन करती थीं। जब उसकी चाची को इस बारे में पता चला, तो वह पूछताछ करने के लिए संजीत पासवान के घर गई, लेकिन संजीत पासवान ने धमकी दी कि वह उन्हें मार देगा और उनके शव गायब कर देगा।

3. पीड़ित के लिखित आवेदन के आधार पर, महिला पी. एस. केस नंबर 42 /2020 दिनांक 15.10.2020 को आई. पी. सी. की धारा 376/34/504/ 506 के तहत और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज किया गया था। जाँच के बाद, जाँच अधिकारी (संक्षेप में 'आई. ओ.') ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अपराधों का संज्ञान विद्वान विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम द्वारा लिया गया था। आरोप तय करने की औपचारिकताओं का पालन करने के बाद, अभियुक्त व्यक्तियों-अपीलार्थियों के खिलाफ तय किए जाने वाले प्रस्तावित आरोपों के बारे में उन्हें समझाया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और मुकदमा चलाने का दावा किया। अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। संजीत पासवान पर आई. पी. सी. की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था, जबकि अपीलार्थी संगीता देवी पर आई. पी. सी. की धारा 376/109 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6/17 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

4. अभियुक्त व्यक्तियों का बचाव यह रहा कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। बचाव पक्ष के अनुसार, पीड़ित के चाचा ने आरोपी संजीत पासवान से कर्ज लिया था और जब आरोपी ने उससे पैसे की मांग की तो पीड़ित लड़की के चाचा ने यह झूठा मामला दर्ज कराया। संगीता देवी का बचाव यह था कि वह निर्दोष थी और पीड़ित के चचेरे भाई, जो इस मामले में पीडब्लू-5 हैं, ने 30, 000/- रुपये का ऋण लिया था जो वह वापस नहीं कर रहा था और जब उसने उससे उस पैसे की मांग की तो उसने उसे इस मामले में फंसाया।

5. अभियोजन पक्ष ने कुल नौ गवाहों की जांच की और प्रदर्श 'पी-1' से लेकर 'पी-16' तक के दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित किए। बचाव पक्ष ने आरोपी संगीता देवी की ओर से एक गवाह से पूछताछ की लेकिन बचाव पक्ष की ओर से कोई दस्तावेजी सबूत प्रदर्शित नहीं किया गया है।

6. अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के गवाहों का पूरा विवरण और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिए जा रहे हैंः

अभियोजन गवाहों की सूची

पीडब्लू-1	पीड़ित ('एक्स')
पीडब्लू-2	आमला देवी
पीडब्लू-3	रामकली देवी
पीडब्लू-4	डॉ. दीप्ति सिन्हा

पीडब्लू-5	पप्पु राय
पीडब्लू-6	अमरेश राय
पीडब्लू-7	डॉ. ज्योत्सना
पीडब्लू-8	आशु कुमार झा
पीडब्लू-9	सरिता चौधरी

बचाव पक्ष के गवाहों की सूची

डीडब्ल्यू-1	बिरजू साह

अदालती गवाहों की सूची

सीडब्ल्यू-1	पूजा कुमारी

प्रदर्शों की सूची

प्रदर्श 'पी-01/पीडब्लू-1'	पीड़ित 'एक्स' का लिखित बयान
प्रदर्श 'पी-02/पीडब्लू-1'	सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़ित 'एक्स' का बयान
प्रदर्श 'पी-03/पीडब्लू-1'	पीड़ित 'एक्स' का लिखित आवेदन एस. एच. ओ. महिला पी. एस. को बच्चे के पितृत्व को स्थापित करने के लिए डी. एन. ए. परीक्षण कराने के लिए दिया जाता है।

प्रदर्श 'पी-04/पीडब्लू-4'	पीड़ित की दंत चिकित्सा रिपोर्ट।
प्रदर्श 'पी-05/पीडब्लू-7'	पीड़ित 'एक्स' की मेडिकल रिपोर्ट
प्रदर्श 'पी-06/पीडब्लू-7'	पीडब्लू-7 द्वारा दंत चिकित्सक को भेजी गई दंत चिकित्सा की माँग
प्रदर्श 'पी-07/पीडब्लू-8'	बच्चे के डीएनए परीक्षण के लिए जैविक नमूना प्रमाणीकरण कार्ड जिसमें आई. ओ., सर्कल अधिकारी, हाजीपुर और पैथोलॉजिस्ट सदर अस्पताल के हस्ताक्षर हैं और इसमें बच्चे की तस्वीर है।
प्रदर्श 'पी-08/पीडब्लू-8'	पीड़ित 'एक्स' के डीएनए परीक्षण के लिए जैविक नमूना प्रमाणीकरण कार्ड जिसमें उसकी तस्वीर और आई. ओ., सर्कल अधिकारी और पैथोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर हैं।
प्रदर्श 'पी-09/पीडब्लू-8'	जैविक नमूना प्रमाणीकरण और डीएनए परीक्षण के लिए

	अभियुक्त संजीत पासवान (ए-1) की तस्वीर और आई. ओ. सर्कल अधिकारी और पैथोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर
प्रदर्श 'पी-10/पीडब्लू-8'	बच्चे के पितृत्व को स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण की एफ. एस. एल. रिपोर्ट
प्रदर्श 'पी-11/पीडब्लू-8'	अदालत को डी. एन. ए. परीक्षण के बारे में जानकारी देते हुए आवरण पत्र
प्रदर्श 'पी-12/पीडब्लू-9'	इस मामले की औपचारिक एफ. आई. आर.

प्रदर्श 'पी-13/पीडब्लू-9'	पीड़ित 'एक्स', आरोपी ए-1 और बच्चे के रक्त का नमूना को डीएनए परीक्षण कराने के लिए भेजने के संबंध में अग्रेषित पत्र
प्रदर्श 'पी-14/पीडब्लू-9'	औपचारिक आरोप-पत्र
प्रदर्श 'पी-15/पीडब्लू-9'	आरोपी ए-2 संगीता देवी की गिरफ्तारी ज्ञापन
प्रदर्श 'पी-16/पीडब्लू-9'	अभियुक्त ए-1 संजीत पासवान का गिरफ्तारी ज्ञापन।

7. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने पर, अभियुक्त व्यक्तियों का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') के तहत दर्ज किया गया, जिसमें अभियुक्त व्यक्तियों ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।

<u>विद्वत विचारण न्यायालय के निष्कर्ष</u>

8. विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की जांच की और प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस मामले में पीडब्लू-1 जो स्वयं पीड़ित है, मामले का प्रमुख गवाह है जो एक चश्मदीद गवाह है। उसने अभियुक्त व्यक्तियों के हाथों पीड़ा झेली है। विद्वत निचली अदालत की राय में, अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह जो पीड़ित ('एक्स') के परिवार के सदस्य हैं, घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं लेकिन उन्होंने कुछ परिस्थितियों का वर्णन किया है जो उन्हें तब मिली जब पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने खुलासा किया कि अपीलार्थी संजीत पासवान द्वारा उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया था। विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियोजक/पीड़ित (पीडब्लू-1) के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की है और पाया है कि पीड़ित एक नाबालिग लड़की है जिसकी माँ मर चुकी है और उसके पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। घटना के समय पीड़ित एक स्कूल जाने वाली बच्ची थी जिसे आरोपी संजीत पासवान ने प्रताड़ित किया था और आरोपी नं. 2 संगीता देवी ने पीड़ित शरीर पर

उस अपराध को करने में सहायता की थी।

9. विद्वत निचली अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के संबंध में दलीलों को खारिज कर दिया क्योंकि अदालत के अनुसार, रिकॉर्ड पर पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं जो प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को दर्शाते हैं और समझाते हैं। विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एफ. आई. आर. दर्ज करने में विलम्ब अपने आप में अवैध नहीं है और हालांकि एफ. आई. आर. का शीघ्र और तत्काल दर्ज करना आदर्श है क्योंकि इससे अभियोजन पक्ष को एक स्पष्ट लाभ मिलेगा, लेकिन विलंबित एफ. आई. आर. के दोष अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक साबित नहीं हो सकते हैं, जब कुछ विलम्ब के साथ एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए विभिन्न प्रकार के वास्तविक कारण हैं। यहाँ, यह ध्यान दिया गया है कि पीड़ित एक ऐसी बच्ची थी जिसकी कोई मां नहीं थी और उसके अवैध पिता थे और लंबे समय से आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसका शोषण किया जा रहा था। वह एक ग्रामीण लड़की थीं और वह शोषण की विशालता को समझने में सक्षम नहीं थी जिससे वह गुजर रही थी। वह भी डर गई/डर के साए में भी थी और इन सभी कारणों से, वह तुरंत पुलिस को मामले की सूचना नहीं दे सकी।

10. विद्वत ट्रायल कोर्ट ने पाया कि डॉक्टर (पीडब्लू-7) द्वारा साबित की गई पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वह अपनी मेडिकल जांच की तारीख पर आठ महीने की गर्भवती थी और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के आधार पर, राय दी गई थी कि वह तैंतीस सप्ताह और दो दिन के भ्रूण को ले जा रही थी। यह सब अभियोजन पक्ष की कहानी को स्थापित करने केपक्ष मे जाता है और तार्किक रूप से प्राथमिकी दर्ज करने में देरी का कारण बताता है। इन कारणों से, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के संबंध में बचाव पक्ष के तर्क को खारिज कर दिया गया है।

11. विद्वत निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का विश्लेषण किया जिसमें पीडब्लू-8 जो सहायक निदेशक, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, पटना हैं और पीड़ित ('एक्स'), आरोपी (ए-1) और बच्चे द्वारा उन्हें प्रदान किए गए रक्त के नमूनों पर डीएनए परीक्षण किया था।डीएनए परीक्षण ने स्थापित किया कि वह पीड़ित और ए-1 बच्चे के जैविक माता-पिता

थे।

12. विद्वत निचली अदालत ने माना कि आरोपी संगीता देवी ने अभियुक्त को अपने घर पर पीड़ित के साथ बलात्कार करने में सुविधा प्रदान करके पीड़िता के शरीर पर बलात्कार करने में सहायता की। निचली अदालत ने आरोपी संजीत पासवान के सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज बयान पर ध्यान दिया जिसमें उसने कहा है कि वह शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे थे। विद्वत निचली अदालत के अनुसार, इससे पता चलता है कि उक्त घटना संजीत पासवान के घर पर नहीं हुई थी क्योंकि विवाहित पत्नी और बच्चे आरोपी के इस कदम का विरोध कर सकते थे।

13. बचाव पक्ष का तर्क है कि प्रदर्श 'पी-04/पीडब्लू-01' के अनुसार पीड़ित की उम्र का पता 17-18 वर्षों के बीच लगाया गया है और पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट जो कि प्रदर्श 'पी-05/पीडब्लू-7' है, से पता चलता है कि पीड़ित की उम्र 17-18 वर्षों के बीच थी। अतः आयु की गणना में त्रुटि का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। हालाँकि, विद्वत विचारण न्यायालय ने बच्चे को जन्म देने की तारीख (29.11.2020) से नौ महीने की गर्भावस्था की अवधि पर ध्यान देते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया। विद्वत विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़ित की आयु अठारह वर्ष से कम थी जब उसके साथ बलात्कार किया गया था। पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 का उल्लेख करते हुए, विद्वत निचली अदालत ने कहा कि धारा 29 का अध्यादेश यह है कि यदि किसी व्यक्ति पर पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 3,5,7 और 9 के तहत कोई अपराध करने या उकसाने या करने का प्रयास करने के लिए मुकदमा चलाया जाता है, तो अदालत को यह मान लेना चाहिए कि अपराध उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जिस पर मुकदमा चलाया जाता है जब तक कि आरोपी इसके विपरीत साबित न हो जाए। हालाँकि, यह धारणा कानून की खंडनकारी धारणा है, लेकिन इसके विपरीत एक जिम्मेदारी/भार/बोझ होगी और यह अभियुक्त के लिए होगा कि वह उक्त धारणा को गलत साबित करके उसका खंडन करे अन्यथा वैधानिक धारणा हमेशा अभियुक्त के खिलाफ होगी।

14. विद्वत विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ए-1 और ए-2 दोनों दोषसिद्धि

के लिए उत्तरदायी हैं और तदनुसार उन्हें दोषी ठहराया और सजा सुनाई जैसा कि ऊपर दिए गए निर्णय में कहा गया है।

2022 की सी. आर. अपील (खं.पी.) संख्या 461 में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ।

15. 2022 की सी. आर. अपील (खं.पी.) संख्या 461 में अपीलार्थी संगीता देवी की विद्वान वकील सुश्री शमा सिन्हा, ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि इस मामले में विद्वत विचारण न्यायालय ने कानून के अनुसार पीड़ित की आयु का निर्धारण नहीं करने में घोर त्रुटि की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुकदमे/विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने गाँव मौदाह, पी. एस. पाटेपुर, जिला-वैशाली में स्थित सरकारी उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक का एक पत्र रिकॉर्ड में रखा, जिसमें जन्म तिथि 29.06.2004 और उसका प्रवेश संख्या 130 दिनांकित 16.05.2019 दिखाया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उक्त प्रधानाध्यापक से पूछताछ नहीं की और न ही उक्त पत्र प्रदर्शित किया गया था, इसलिए, विद्वत निचली अदालत ने विवादित फैसले के पैराग्राफ '28' में स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि अदालत इस पर विचार नहीं करेगी। स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र की ज़ेरॉक्स प्रति रिकॉर्ड में लाई गई थी लेकिन मूल प्रस्तुत नहीं की गई थी और न ही ज़ेरॉक्स प्रति प्रदर्शित की जा सकी थी।पीड़ित की सदर अस्पताल में 16.10.2020 को चिकित्सकीय जांच की गई, उस समय वह आठ महीने की गर्भवती थी और अगले महीने 29.11.2020 को उसने एक बच्चे को जन्म दिया। दिनांक 16.10.2020 को, उसकी उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच होने का पता चला। विद्वत ट्रायल कोर्ट इस बात की सराहना नहीं कर सका कि मुकदमे/विचारण के दौरान, इस बिंदु पर जिन डॉक्टरों की जांच/परीक्षा की गई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अल्ट्रासाउंड, रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट और डेंटल रिपोर्ट के आधार पर, पीड़ित की उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच निर्धारित की गई थी।इस संबंध में, डॉक्टर (पीडब्लू-4) के साक्ष्य को इस अदालत के समक्ष यह प्रदर्शित करने के लिए रखा गया है कि डेंटल डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित की सही उम्र का पता नहीं लगाया जा सका है। उसके बयान के पैराग्राफ '9' में, पीडब्लू-4 ने कहा है कि डेंटल रिपोर्ट के आधार पर कोई भी पीड़ित की सही उम्र नहीं कह सकता है।

16. विद्वान वकील ने **राम विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जो **(2021) 15 एस. सी. सी. 241** में रिपोर्ट किया गया है, यह प्रस्तुत करने के लिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किशोर न्याय(बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (इसके बाद '2007 नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 12 (3) (बी) में निर्धारित प्रक्रिया, व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 94 के प्रावधानों से भौतिक रूप से अलग नहीं है। इसमें मामूली बदलाव हैं क्योंकि नियम 12 (3) (ए) (आई)/(i) और (ii) को भाषा में मामूली बदलाव के साथ जोड़ा गया है। अधिनियम की धारा 94 में बच्चे या किशोर को दी जाने वाली आयु सीमा के लाभ के संबंध में प्रावधान नहीं हैं जैसा कि 2007 के नियमों के नियम 12 (3) (बी)/(ख) में प्रदान किया गया था, हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अधिनियम की धारा 94 के अधिनियमन के साथ अस्थिकरण परीक्षण के महत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अस्थीकरण परीक्षण की विश्वसनीयता असुरक्षित बनी हुई है जैसा कि 2007 के नियमों के नियम 12 के तहत था। इन टिप्पणियों के बल पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च द्वारा **रजक मोहम्मद बनाम एच. पी. (हिमाचल प्रदेश)** राज्य के मामले में, जो **(2018) 9 एस. सी. सी. 248** के पैरा '9' मेंजो अवलोकन किया गया है, वह अभी भी अच्छा/सही रहेगा और यह माना जाना चाहिए कि इस मामले में दंत चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर आयु निर्धारण एक सटीक निर्धारण नहीं होगा, किसी भी तरफ से/दोनों तरफ पर्याप्त अंतर/मार्जिन की अनुमति दी जानी चाहिए।

17. विद्वान वकील ने आगे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जो कि **कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन/अपने स्वयं के प्रस्ताव पर न्यायालय बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य (सी. आर. एल. रेफ. 2/2024 निर्णय दिनांक 02.04.2024)** के मामले में था, जिसमें माननीय खंड पीठ ने दक्षिण जिला साकेत अदालत, नई दिल्ली के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एससी-पॉक्सो) की अदालत से

सीआरपीसी की धारा 395 (2) के तहत दिए गए एक संदर्भ का जवाब दिया।कानून का सवाल/प्रश्न नीचे पढ़ा गया हैः.

> "(i) क्या पॉक्सो मामलों में, अदालत को आयु अनुमान रिपोर्ट के निचले स्तर पर विचार करने की आवश्यकता है, या उन मामलों में पीड़ित की आयु अनुमान रिपोर्ट के ऊपरी स्तर पर विचार करने की आवश्यकता है जहां पीड़ित की आयु अस्थि आयु अस्थिकरण परीक्षण के माध्यम से साबित होती है?
>
> (ii) पॉक्सो अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में जहां पीड़ित की उम्र को अस्थि आयु अस्थिकरण परीक्षण के माध्यम से साबित किया जाना है, क्या 'त्रुटि का अंतर' का सिद्धांत लागू होना है या नहीं।"

18. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि उक्त संदर्भ का उत्तर देते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि कानूनी स्थिति उचित रूप से तय की गई है और काफी स्पष्ट है। पॉक्सो मामलों में, अदालत को पीड़ित की उम्र में दो साल की त्रुटि का अंतर लागू करने की आवश्यकता होगी। माननीय खण्डपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि यौन हमले के मामले में जहां भी न्यायालय को अस्थिकरण परीक्षण के आधार पर पीड़ित की आयु निर्धारित करने के लिए कहा जाता है, संदर्भ में दी गई ऊपरी आयु को पीड़ित की आयु माना जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जाना है, तो वर्तमान मामले में, पीड़ित ('एक्स') की आयु 18 वर्ष के रूप में ली जानी चाहिए।

19. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि लिखित आवेदन जो वर्तमान मामले का आधार है, अभियोजक के अनुसार पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा लिखा गया था। अपने बयान में, उसने पैराग्राफ '6' में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपनी चाची के साथ महिला पुलिस स्टेशन गई थी और पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सब कुछ बताया था, जिन्होंने उसका बयान दर्ज किया था और उसने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इस मामले में प्रभारी अधिकारी सरिता चौधरी से पीडब्लू-9 के रूप में पूछताछ की गई है। जब उससे यह सवाल पूछा गया कि क्या उसने लिखित आवेदन लिखा था, तो पीडब्लू-9 ने बयान दिया कि उसने आवेदन

नहीं लिखा था, बल्कि पीड़ित एक लिखित आवेदन के साथ पुलिस स्टेशन आई थी और वह यह नहीं कह सकती कि आवेदन किसने लिखा था। उक्त आवेदन पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं और न तो तारीख और न ही वर्ष का उल्लेख किया गया है।उसने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पीड़िता का बयान दर्ज किया था।

20. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि लिखित आवेदन को मात्र/केवल पढ़ने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि पहली बार में, उन्होंने आरोप लगाया है कि संगीता देवी और उनकी बेटी, दोनों के कहने पर और उनके प्रलोभन पर, उन्हें संजीत पासवान के घर ले जाया जा रहा था। संजीत पासवान ने उसे पैसे देने का लालच दिया और उसके साथ बलात्कार किया जिसका उसने विरोध किया लेकिन उसने उसे धमकी दी कि अगर वह इस बारे में किसी को बताएगी तो उसे मार दिया जाएगा, इसलिए उसने इसका खुलासा किसी को नहीं किया। पीड़िता के अनुसार, इस प्रकार, घटना की जगह/स्थान संगीता देवी का घर नहीं बल्कि संजीत पासवान का घर था, लेकिन मुकदमे/विचारण के दौरान, पीड़ित ने घटना की जगह बदल दी है। उसने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह आंचल कुमारी के साथ अपने स्कूल से आती-जाती थी, जो उसे अपने घर ले जाती थी, जहाँ उसकी माँ उसे एक कमरे में ले जाती थी और वहाँ पहले से ही एक लड़का मौजूद था, जिसने उसके साथ गलत काम किया और उसके साथ बलात्कार करने के बाद, उसने उसे धमकी दी कि अगर वह अपनी चाची को इस बारे में बताएगी तो उसे मार दिया जाएगा। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि पीडब्लू-1 के साक्ष्य के केवल अवलोकन पर, यह प्रतीत होता है कि उन्होंने घटना स्थल को बदल दिया है और संगीता देवी के घर की उनकी यात्रा की कहानी विश्वास को प्रेरित नहीं करेगी। संगीता देवी की बेटी आंचल कुमारी को जांच के चरण में ही आरोपमुक्त कर दिया गया है क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिली है। यहां तक कि अपने मुख्य परीक्षण में भी, पीडब्लू-1 ने यह नहीं कहा है कि संगीता देवी ने उसे संजीत पासवान के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए कहा था या उसने उसे किसी भी बहाने से लुभाया था। हालाँकि उन्होंने कहा है कि संजीत पासवान और संगीता देवी ब्याज के आधार पर धन के लेन-देन में शामिल थे, लेकिन आई. ओ. ने कहा है कि

उनके साक्ष्य के दौरान, उन्हें इस मुद्दे पर कोई गवाह नहीं मिला था।

21. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि पीडब्लू-1 के साक्ष्य के एक मात्र/केवल अवलोकन से पता चलता है कि उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से कम से कम तीन महीने पहले गर्भावस्था के बारे में पता चला था। अपने बयान के पैराग्राफ '4' में, उसने कहा है कि जब वह गर्भवती हुई, तो उसके कुछ दिनों बाद उसकी चाची ने संदेह जताया था क्योंकि उसकी शारीरिक विशेषता बदल रही थी। उसने कहा है कि उसकी चाची ने उससे इसके बारे में पूछा था और उसने उसे इस तथ्य का खुलासा किया था। इसलिए, उसके बयान से यह स्पष्ट है कि उसके गर्भ धारण करने के कुछ ही दिनों बाद, उसकी चाची को भी गर्भावस्था के बारे में पता चला था, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। उसने बच्चे के जन्म से लगभग डेढ़ महीने पहले 15.10.2020 को लिखित आवेदन जमा किया था। उसने अपने बयान के पैराग्राफ '25' में कहा है कि पुलिस स्टेशन में लिखित आवेदन जमा करने से कम से कम तीन महीने पहले, उसे गर्भावस्था के बारे में पता था/जानती थी। पैराग्राफ '26' में उसने कहा है कि जानकारी के बाद भी उनके चाचा या भाई संजीत पासवान के पास नहीं गए। पैराग्राफ '28' में उसने कहा है कि वह छह महीने के दौरान कम से कम 5-6 बार संजीत पासवान के घर गई थीं। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि पैराग्राफ '27' में पीडब्लू-1 का बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भले ही संजीत पासवान शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे थे, लेकिन अभियोजक/अभियोजिका नियमित रूप से उसके घर जाती थी और वह खुद दावा करती है कि वह कम से कम 5-6 मौकों पर संजीत पासवान के घर गई थी, इसलिए, विद्वत निचली अदालत का यह निष्कर्ष कि पीड़ित संजीत पासवान के घर नहीं जा सकती थी क्योंकि वह शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे थे और उन्होंने उसका विरोध किया होता, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर आधारित नहीं है।

<u>2022 की सी. आर. अपील (डी. बी.) संख्या 546 में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ।</u>

22. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री मनीष कुमार सं.2 ने प्रस्तुत किया है कि विद्वत निचली अदालत अपने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से यह समझने में विफल रही कि यह बलात्कार का मामला नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों द्वारा सहमति से संबंध विकसित किया गया था। यह

उसका निवेदन/कहना है कि पीड़ित ने कभी नहीं कहा कि उसने अपीलार्थी के साथ यौन संभोग के समय विरोध किया था।

23. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि डॉक्टर ने पीड़ित की जांच की और उसकी उम्र का आकलन 17-18 वर्षों के बीच किया, इसलिए, वह वास्तव में व्यस्क थी और इसके बावजूद परिणामों को समझने की स्थिति में थी कि सहमति से उसने अपीलार्थी के साथ संबंध विकसित किया।

24. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि यदि ऐसा अवसर आता है तो सजा के बिंदु पर एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ।

<u>अभियोजन की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

25. राज्य की विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक सुश्री शशि बाला वर्मा ने अपीलों का विरोध किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने पाया है कि अभियोजक/अभियोक्ता/पीड़ित घटना के समय 18 वर्ष से कम आयु का नाबालिग थी। उसे संगीता देवी ने लुभाया जो उसे अपने घर ले गई जहां संजीत पासवान ने उसे पैसे देने के बहाने उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद, उसे संजीत पासवान के साथ बार-बार शारीरिक संबंध स्थापित करने और यौन कृत्य/संबंध बनाने के लिए यह धमकी देते हुए मजबूर किया गया कि अगर वह इस बारे में किसी को बताएगी तो उसे मार दिया जाएगा।

26. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख पर अभियोजन पक्ष के मामले को सभी उचित संदेहों से परे स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष/अभियोजिका के साक्ष्य के रूप में पर्याप्त और ठोस सामग्री है। जहाँ तक वर्तमान अपील में संजीत पासवान की याचिका का संबंध है, यह केवल एक बाद का विचार है क्योंकि प्रतिपरीक्षा के पैटर्न से यह प्रतीत होगा कि उन्होंने कभी भी पीड़ित/अभियोजक/अभियोजिका को यह सुझाव नहीं दिया कि यह सहमति से किया गया यौन संबंध था। वास्तव में, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में, संजीत पासवान ने पीड़िता के साथ अपनी जान-पहचान से पूरी तरह से इनकार किया है और कहा है कि उसने कभी भी उसके साथ कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया था।

विचारणीय

27. हमने दोनों अपीलों में अपीलार्थी के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक को सुना है और साथ ही निचली अदालत के रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया है।

28. सबसे पहले, हम अभियोजक/अभियोजिका/पीड़ित की उम्र के संबंध में साक्ष्यों को ध्यान में रखेंगे, जिसकी वर्तमान मामले में पीडब्लू-1 के रूप में जांच की गई है। अभियोजक/अभियोजिका ने अपने फ़र्दबेयान में उसकी उम्र 16 वर्ष बताई है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया था जिसमें उसने फिर से अपनी उम्र 16 साल होने का दावा किया है। जैसा कि विद्वत विचारण न्यायालय के निर्णय से प्रतीत होता है, अभियोजन पक्ष/अभियोजिका की आयु को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने गाँव-मौदह, पी. एस.-पाटेपुर, जिला-वैशाली में स्थित सरकारी उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक से एक पत्र रिकॉर्ड में लाया गया जिसमें अभियोजक/अभियोजिका की जन्म तिथि 16.05.2019 दिनांकित प्रवेश संख्या 130 के अनुसार 29.06.2004 के रूप में दिखाई गई है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने स्कूल के प्रधानाध्यापक से पूछताछ नहीं की और उक्त पत्र को प्रदर्शित नहीं किया गया है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एक ज़ेरॉक्स प्रति रिकॉर्ड पर लाई गई थी लेकिन मूल प्रस्तुत नहीं की गई थी।ऐसी स्थिति में चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई आयु महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर (पीडब्लू-4) को सदर अस्पताल, हाजीपुर में दंत चिकित्सक के रूप में तैनात किया गया था। उन्होंने पीड़ित के दांतों की उम्र का पता लगा लिया है। उनके अनुसार, दांतों की उम्र 17-18 वर्षों के बीच है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट को साबित कर दिया है जिसे प्रदर्श '4' के रूप में चिह्नित किया गया है। पीडब्लू-4 और प्रदर्श '4' के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जब हम इस मामले पर पीड़ित की उम्र के बिंदु पर विचार करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय **राम विजय सिंह** (ऊपर) और **रजक मोहम्मद** (ऊपर) दोनों मामले में यह एक दृष्टिकोण लेने के लिए प्रेरित करेगा कि प्रकट की गई दंत आयु की विश्वसनीयता कमजोर बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति में, माननीय दिल्ली उच्च

न्यायालय का अपने स्वयं के प्रस्ताव पर न्यायालय/**कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र** (उपरोक्त) के मामले में निर्णय प्रेरक प्रतीत होता है। उक्त मामले में, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित की अनुमानित आयु 16-18 वर्ष थी। मुद्दा यह था कि क्या पीड़ित की उम्र को निचले हिस्से/स्तर में लिया जाना चाहिए या सीमा के ऊपरी हिस्से/स्तर में। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि अदालत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और क्या दोनों तरफ कोई और "त्रुटि का अंतर" भी लागू किया जाना चाहिए, जिससे आयु सीमा 16 से 18 वर्ष से 14 से 20 वर्ष हो जाए ।उक्त निर्णय के पैराग्राफ '23' और '24' को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः.

> "23. हम इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकते कि हम कानून की प्रतिकूल प्रणाली का पालन कर रहे हैं जहां निर्दोषता का अनुमान/धारणा अनिवार्य दर्शन है। हालाँकि किसी भी आपराधिक मुकदमे में, प्रयास सच्चाई तक पहुँचने का होता है, प्रतिकूल प्रणाली में, न्यायाधीश आम तौर पर एक अंपायर की तरह कार्य करता है जो देखता है कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम है या नहीं। चूँकि भारत में प्रतिकूल प्रणाली 'अभियुक्त की निर्दोषता' पर आधारित है, इसलिए सबूत का भार, आम तौर पर, अभियोजन पर पड़ता है।हमारी आपराधिक प्रणाली निर्धारित करती है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ मामला संदेह से परे साबित होना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि संदेह का कोई तत्व है, तो ऐसा लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए।
>
> 24. मान लीजिए/यह स्वीकार करते हुए कि किसी भी किशोर अपराधी के संदर्भ में, बचाव पक्ष का प्रयास हमेशा 'निचले पक्ष/स्तर' से त्रुटि की सीमा की तलाश करना होगा क्योंकि यह ऐसे अपराधी के लिए फायदेमंद साबित होगा जो कानून के साथ संघर्ष में किशोर के रूप में व्यवहार करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा, जिससे वह सजा के पहलू सहित कई तरीकों से उचित सुरक्षा प्राप्त करने का हकदार बन जाएगा। इस प्रकार, हालांकि अदालतें यह देखने के लिए उत्साही हैं कि एक किशोर को जेजे अधिनियम के प्रावधानों का लाभ मिले, लेकिन साथ ही अदालतों के लिए यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है कि गंभीर अपराध करने के दंड से बचने के लिए बेईमान व्यक्तियों द्वारा इस तरह के संरक्षण और विशेषाधिकारों का दुरुपयोग न किया जाए।"

29. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने **श्वेता गुलाटी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य , 2018 में एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 10448** में रिपोर्ट किया गए, के मामले में अभिनिर्धारित किया कि ऊपरी आयु पर विचार किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा

सके कि अभियुक्त किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो। न्यायालय का विचार था कि यदि कोई अनिश्चितता है, तो संदेह का लाभ केवल अभियुक्त और अभियुक्त को ही मिलना चाहिए। **राजू यादव बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य के एक अन्य मामले में, जो 2023 में एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2782** रिपोर्ट किया गया, एक परस्पर विरोधी दृष्टिकोण लिया गया था। इस समय, न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्य पर ध्यान दिया और कहा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित बच्चे की उम्र का निर्धारण करते हुए, न्यायालय का झुकाव त्रुटि के निचले स्तर पर विचार करने की ओर होना चाहिए क्योंकि यह पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के दो निर्णयों में टकराव/संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, माननीय न्यायालय ने **राज्य बनाम बसीर अहमद** के मामले में अपने स्वयं के खंड पीठ के फैसले को संदर्भित किया, जो **2023 में एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 5852** में बताया/रिपोर्ट किया गया था, जिसमें समान मुद्दा विचार के लिए उठा था। उक्त मामले में, यौन उत्पीड़न करने के लिए मुकदमे का सामना कर रहे आरोपी को विद्वत निचली अदालत ने यह देखते हुए बरी कर दिया कि अभियोजक/अभियोजिका की उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच दिखाई गई थी और इसलिए, कथित अपराध के समय उसके नाबालिग होने का कोई निर्णायक सबूत नहीं था। यह लाभ उस अभियुक्त को दिया गया जिसे बरी कर दिया गया था। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने न केवल अस्थीकरण रिपोर्ट के ऊपरी हिस्से/स्तर में आयु पर विचार करने का तथ्य को बरकरार रखा बल्कि ऐसी उच्च अनुमानित आयु को दो साल का और अंतर देने के सिद्धांत को भी मंजूरी दी। उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश यहाँ पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैंः.

> "12. इस प्रकार जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या अस्थिकरण परीक्षण में अनुशंसित निचली या ऊपरी आयु को अभियोजक/अभियोजिका की आयु के रूप में अपनाया जाना चाहिए। यदि सभी परिस्थितियों में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना है, तो यह उच्च सीमा है जो ली जानी है और लाभ बढ़ाया जाना है जैसा कि **त्रिवेणीबेन बनाम गुजरात राज्य (1989) 1 एस. सी. सी. 678 और मारू राम बनाम भारत संघ (1981) 1 एस. सी. सी. 107** के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है। तो ऐसा मामला होने पर/के कारण, हम अभियोजक की आयु की सीमा को 17 से 19 वर्ष मान सकते हैं जैसा कि अस्थिकरण परीक्षण में दिया गया है। दोनों तरफ दो साल के त्रुटि सिद्धांत को

> लागू करते हुए, अभियोजक/अभियोजिका की आयु 15 से 21 साल के बीच कुछ भी हो सकती है। भले ही त्रुटि का अंतर उच्च स्तर पर न हो, ऑसिफिकेशन/अस्थिकरण परीक्षण द्वारा आयु की ऊपरी सीमा का अनुमान 19 वर्ष के रूप में लगाया गया है। लाभ देते हुए, अभियोजक/अभियोजिका की आयु 19 वर्ष मानी जानी चाहिए। न्यायालय द्वारा इसी तरह का/समान निष्कर्ष श्वेता गुलाटी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 10448 के मामले में निकाला गया था। इस प्रकार हम पाते हैं कि विद्वान ए. एस. जे. ने घटना के समय अभियोजिका के वयस्क होने को सही मान लिया है। हम अभियोजिका की उम्र के संबंध में निष्कर्षों में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं।"

30. हम यह भी पाते हैं कि रजक मोहम्मद (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ '9' में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

> "9. हालांकि यह सही है कि रेडियोलॉजिकल परीक्षा के आधार पर निर्धारित उम्र एक सटीक निर्धारण नहीं हो सकता है और किसी भी तरफ से पर्याप्त अंतर की अनुमति दी जानी चाहिए, फिर भी रेडियोलॉजिकल परीक्षा की रिपोर्ट के साथ ऊपर बताए गए तथ्यों की समग्रता अभियोजिका की सही उम्र के संबंध में पर्याप्त संदेह के लिए जगह छोड़ती है। उपरोक्त संदेह का लाभ स्वाभाविक रूप से अभियुक्त के पक्ष में जाना चाहिए।"

31. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हमारी राय है कि वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष निर्णायक रूप से यह साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियोजिका कथित घटना की तारीख को नाबालिग थी। लाभ अभियुक्त को जाएगा। ऐसी परिस्थिति में, दोनों अपीलार्थी पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप से बरी होने के हकदार होंगे, जिससे उन्हें संदेह का लाभ मिलेगा।

32. यह हमें दूसरे आरोप पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। अपीलार्थी संगीता देवी पर आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एन)/109 के तहत आरोप लगाया गया है।

33. अभियोजिका (पीडब्लू-1) ने कहा है कि यह घटना पिछले साल दुर्गा पूजा से पहले उसके साथ हुई थी। घटना से पहले, वह आंचल कुमारी के साथ स्कूल जाती थी। आंचल कुमारी उसे अपने घर ले गई थी जहाँ उसकी माँ पीड़िता को एक कमरे में ले गई थी, उसने वहाँ एक लड़के को बुलाया था जिसका नाम संजीत पासवान था और उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। इसके बाद, दोनों ने उसे धमकी दी कि अगर वह अपनी चाची को इस बारे में

बताएगी तब उसे मार दिया जाएगा। उसने कहा है कि संजीत पासवान नियमित रूप से उसके साथ बलात्कार करता था, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। जब उससे पूछा गया कि क्या महिला पुलिस स्टेशन में उसके लिखित आवेदन में उसने कहा था कि वह स्कूल जाती थी, तो पीड़िता ने कहा कि उसे याद नहीं है। हम लिखित आवेदन (प्रदर्श '1') से पाते हैं कि अभियोजिका ने यह नहीं कहा है कि वह स्कूल जाती थी। उसने कहा है कि संगीता देवी और उसकी बेटी आंचल कुमारी दोनों ने उसे लुभाया और उसे संजीत पासवान के घर ले गए, जहाँ संजीत पासवान ने पैसे देने के नाम पर उसे लुभाया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने कहा है कि जब उसने विरोध किया, तो उसने उससे कहा कि अगर वह किसी को बताएगी, तो उसे मार दिया जाएगा। उसके लिखित आवेदन और मुकदमे के दौरान साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पीडब्लू-1 ने घटना स्थल के संबंध में अपना बयान बदल दिया है, जहां पहली बार उसके साथ बलात्कार किया गया था। अपने लिखित आवेदन में, उसने यह नहीं कहा है कि वह अपने स्कूल जाती थी और आंचल कुमारी के साथ वापस आती थी, लेकिन अपने मुख्य परीक्षा में, उसने दावा किया है कि वह आंचल कुमारी के साथ स्कूल आती और जाती थी और एक दिन आंचल कुमारी उसे अपने घर ले गई थी। अपने लिखित आवेदन में, अभियोजिका ने कहा है कि संगीता देवी और आंचल कुमारी दोनों ने उसे लुभाया और उसे अपने घर (संजीत पासवान के घर) ले गए। धमकी के मामले में भी, जबकि अपने लिखित आवेदन में, उसने कहा है कि यह संजीत पासवान था जिसने उसे धमकी दी थी, मुकदमे में अपने साक्ष्य में, उसने कहा है कि बलात्कार के बाद, संगीता देवी और संजीत पासवान ने उसे धमकी दी थी। इसलिए, हम पाते हैं कि पी. डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य में संजीत पासवान के साथ उसकी पहली मुलाकात और फिर उस घटना के स्थान के संबंध में एक भौतिक/महत्वपूर्ण विसंगति है जहां उसके साथ बलात्कार किया गया/हुआ था। यह उनके बयान से भी स्पष्ट है कि छह महीने की अवधि के दौरान, वह 5-6 मौकों पर संजीत पासवान के घर गई थीं। एफ. आई. आर. दर्ज करने से कम से कम तीन महीने पहले उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में पता था।

34. हमने देखा है कि जब संगीता देवी की ओर से जिरह शुरू हुई, तो आरोपी के

विद्वान वकील जिरह करने के लिए उपस्थित नहीं हुए। विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिलिखित किया कि अभियुक्त संजीत पासवान के वकील द्वारा पीड़ित से जिरह की गई थी और यह 3:00 बजे थे, इसलिए अदालत ने पीड़िता के बयान/गवाही को बंद कर दिया और उसे आरोपमुक्त कर दिया। अभिलेख पर, संगीता देवी की ओर से उनके वकील के माध्यम से पीड़ित को प्रतिपरीक्षा के लिए वापस बुलाने के लिए 07.09.2021 दिनांकित एक आवेदन दायर किया गया है, इसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को दी गई प्रतीत होती है। विद्वत विचारण न्यायालय का दिनांकित 07.09.2021 का आदेश उक्त आवेदन को दाखिल करने को स्वीकार करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आवेदन को दबाया गया था, लेकिन दिनांक 01.10.2021 के आदेश के अनुसार, विद्वत निचली अदालत ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। अदालत का विचार था कि आरोपी द्वारा दायर आवेदन केवल अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग था ताकि मामले को आगे बढ़ाया जा सके। हम अभिलेख पर साक्ष्य से पाते हैं कि पीडब्लू-1 को वापस बुलाने के लिए आवेदन तब दायर किया गया था जब अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ की जा रही थी।पीडब्लू-7 की जाँच 27.08.2021 पर की गई थी, पीडब्लू-8 की जाँच 24.09.2021 पर की गई थी और पीडब्लू-9 की जाँच 03.12.2021 पर की गई थी, इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, विद्वत निचली अदालत की यह टिप्पणी कि पीडब्लू-1 को वापस बुलाने के लिए आवेदन आरोपी संगीता देवी की ओर से केवल मामले को आगे बढ़ाने के लिए दायर किया गया था, का कोई आधार नहीं है। ऐसा करके, विद्वत निचली अदालत ने उसे केवल पीडब्लू-1 से जिरह करने से वंचित कर दिया जो इस मामले का प्रमुख गवाह है। हमारी राय में, इसने संगीता देवी (2022 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 461 में अपीलार्थी) के बचाव को गंभीर रूप से प्रतिकूल बना दिया है।

35. जैसा कि हमने ऊपर देखा है, घटना स्थल के संबंध में पीड़ित (पीडब्लू-1) के बयान में भौतिक/महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं, इस अदालत की यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि संगीता देवी ने पीड़िता पर बलात्कार की कथित घटना को सुगम बनाया था। इसलिए हम संगीता देवी को आई. पी. सी. की धारा

376(2)(एन)/109 के तहत आरोप से बरी कर देंगे, उसे संदेह का लाभ देते हुए।यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

36. जहाँ तक 2022 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 546 में अपीलार्थी संजीत पासवान का संबंध है, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि अभियोजिका ने एक वयस्क लड़की होने के नाते अपीलार्थी के साथ सहमति से संबंध विकसित किया था और उसने कभी भी यौन संभोग के समय कोई विरोध नहीं किया था। उसने 5-6 मौकों पर अपीलार्थी के घर जाने की बात स्वीकार की है।

37. हम अभियुक्त संजीत पासवान की ओर से अभियोजिका की प्रतिपरीक्षा के पैटर्न से पाते हैं कि बचाव पक्ष द्वारा उन्हें कभी यह सुझाव नहीं दिया गया था कि यह एक सहमति वाला संबंध था। उसे सुझाव दिया गया था कि संजीत पासवान ने उसके साथ कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया था, जिससे उसने इनकार किया और कहा कि संजीत पासवान ने उसके साथ गलत काम किया था। बचाव पक्ष ने उसे सुझाव दिया कि उसके चाचा ने संजीत पासवान से ऋण लिया था और जब संजीत पासवान ने उक्त ऋण राशि की मांग की, तो उसके चाचा ने उसे एक झूठे मामले में फंसाया। अभियोजिका ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया। पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 पीडब्लू-1 के परिवार के सदस्य हैं जो सुनी-सुनाई गवाही देते हैं और जैसा कि पीडब्लू-1 द्वारा खुलासा किया गया है। पीडब्लू-5 पीड़ित का चचेरा भाई है। पीडब्लू-6 पीड़ित का सगा भाई है और वह गुवाहाटी में रहता है और उसे अपनी चाची, बहन और ग्रामीणों से जो पता चला, उसके आधार पर उसने गवाही दी थी। पीडब्लू-7 वह डॉक्टर है जिसने हाजीपुर के सदर अस्पताल में 16.10.2020 को पीड़ित की जांच की थी। उसने पीड़िता को आठ महीने की गर्भवती पाया था। उन्होंने रेडियोलॉजिकल जांच के आधार पर यह भी राय दी है कि पीडब्लू-1 की आयु 17-18 वर्ष के बीच थी।

38. आशु कुमार झा (पीडब्लू-8) फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, पटना के सहायक निदेशक हैं। उन्हें डीएनए अनुभाग में तैनात किया गया था। उन्होंने कहा है कि आई.ओ./कोर्ट के आदेश से, उन्होंने पीड़ित, आरोपी संजीत पासवान और पीड़ित के शिशु बच्चे को डीएनए से

मिलान करने के लिए एकत्र किए थे, रक्त का नमूना सदर अस्पताल, हाजीपुर के डॉक्टर के माध्यम से एफएसएल के जैविक नमूना कार्ड के प्रारूप पर लिया गया था। उन्होंने शिशु, पीड़ित और आरोपी के डीएनए परीक्षण के लिए जैविक नमूना प्रमाणीकरण कार्ड को क्रमशः प्रदर्श '7', '8' और '9' के रूप में साबित किया है। डी. एन. ए. परीक्षण में जो निष्कर्ष निकला है वह यह है कि 'I' (रक्त स्रोत-संजीत पासवान) और 'II' (रक्त स्रोत-पीड़ित) के रूप में चिह्नित प्रदर्श के स्रोत, 'III' (रक्त स्रोत-शिशु) के रूप में चिह्नित प्रदर्श के स्रोत के जैविक माता-पिता पाए गए हैं। उन्होंने कोड संख्या 040478 वाली रिपोर्ट को साबित कर दिया है जिस पर उन्होंने प्रदर्श '10' के रूप में 19.08.2021 को अपने हस्ताक्षर किए थे। ।प्रदर्श '10' से यह स्पष्ट है कि आरोपी और पीड़ित, बच्चे के जैविक माता-पिता हैं।

39. आई. ओ. (पीडब्लू-9) ने औपचारिक एफ. आई. आर. (प्रदर्श '12') को साबित कर दिया है। वह पीड़िता को चिकित्सा उपचार के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल ले गई थी और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान भी दर्ज कराया था। उन्होंने डीएनए टेस्ट भी करवाया था। आई. ओ. ने उनके द्वारा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, पटना को लिखे गए पत्र को प्रदर्श '13' के रूप में साबित कर दिया है।

40. संजीत पासवान का बयान धारा 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं और वह पीड़ित को नहीं जानते थे। उसने यह भी कहा है कि उसने पीड़ित के साथ कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया था।

41. अभिलेख पर मौजूद सभी साक्ष्यों से हम पाते हैं कि बचाव पक्ष ने कभी भी पीड़ित के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने का अनुरोध नहीं किया। अपीलार्थी संजीत पासवान को बच्चे का जैविक पिता पाया गया है और अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी संजीत पासवान के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 376(2)(एन) के तहत अपना मामला स्थापित किया है। अपीलार्थी संजीत पासवान की धारा 376(2)(एन) के तहत दोषसिद्धि कायम है।

42. हम पाते हैं कि विद्वत निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जिसका अर्थ होगा दोषी संजीत पासवान के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और उसे

पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। आई. पी. सी. की धारा 376(2)(एन) के तहत दंडनीय अपराध के लिए उन पर कोई सजा नहीं लगाई गई है। चूँकि इस न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है, इसलिए इस अपराध के लिए अपीलार्थी पर लगाई गई सजा को रद्द किया जा सकता है।

43. धारा 376(2)(एन) के तहत किए गए अपराध के लिए, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलार्थी संजीत पासवान की पत्नी और तीन बच्चे हैं, जो पूरी तरह से उस पर निर्भर हैं, उसे उचित रूप से दंडित किया जा सकता है और मामले पर उचित विचार किया जा सकता है। चूंकि धारा 376(2)(एन) में न्यूनतम दस साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन यह आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

44. पूरी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि अपीलार्थी संजीत पासवान को चौदह साल की कठोर शारीरिक कारावास की सजा अपराध की स्थिति के अनुरूप होगी। हम, तदनुसार, उसे आई. पी. सी. की धारा 376(2)(एन) के तहत दंडनीय अपराध के लिए 50,000/- रुपये के जुर्माने के साथ चौदह साल के कठोर कारावास की सजा देते हैं।

45. 2022 की सी. आर. अपील(खं.पी.) संख्या 546 की आंशिक रूप से स्वीकृति दी जाती है।

46. निचली अदालत/विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड/अभिलेखों को फैसले की एक प्रति के साथ विद्वत निचली अदालत/विचारण न्यायालय को भेजा जाएगा।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायामूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायामूर्ति)

सुष्म 2/ऋषि -

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।